



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

No. 67]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2006/चैत्र 29, 1928

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2006/CHAITRA 29, 1928

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 13 अप्रैल, 2006

सं. टीएएमपी/15/2005-एनएसआईसीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा न्हावा शेवा इन्टरेशनल कन्टेनर टर्मिनल लिमिटेड के दरमान से संबंधित दिनांक 22 जुलाई, 2005 के अपने पिछले आदेश की, संलग्न आदेशानुसार, समीक्षा करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/15/2005 - एनएसआईसीटी

आ दे श

(मार्च 2006 के 7 वें दिन पारित)

न्हावा शेवा इन्टरनेशनल कन्टेनर टर्मिनल (एनएसआईसीटी) के दरमान से संबंधित दिनांक 22 जुलाई 2005 के आदेश की, जो भारत के राजपत्र में 3 अगस्त 2005 को प्रकाशित हुआ था; समीक्षा करने के बाद प्रशुल्क का निर्धारण करते हुए यह आदेश जारी किया जाता है। 22 जुलाई 2005 का आदेश इस तथ्य के लिए आवश्यक हो गया था कि पिछले प्रशुल्क निर्धारण के लिए इस प्राधिकरण ने, एनएसआईसीटी द्वारा इस प्राधिकरण के सम्बन्ध प्रस्तुत यातायात पर आधारित, अनुमानित राजस्व पर विवार किया था और यह पाया गया था कि उस अवधि में देखे गए वास्तविक यातायात की तुलना में अनुमान बहुत कम था। तथापि, बार-बार अनुरोधों के बाद भी, पिछली समीक्षा के समय एनएसआईसीटी ने कोई ढाटा या सूचना उपलब्ध नहीं करवाई और इसलिए यह समीक्षा इस प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना, जेनपीटी से प्राप्त किए गए उपयुक्त विवरण और 2000 में प्रशुल्क निर्धारण के समय, पिछली बार एनएसआईसीटी द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण के आधार पर की गई थी। वर्ष 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 के लिए लाभत रिश्तियों का विश्लेषण ने, नियोजित पूँजी पर अनुमेय प्रतिलाम की वस्तु के अतिरिक्त 30.20% औसत राजस्व अधिशेष दिखाया था। कठिन आदेश में वर्णित कारणों से, इस प्राधिकरण ने, पिछली दरों में लगभग 12.85% की कमी करते हुए प्रमाणशाली ढंग से संशोधित प्रशुल्क का निर्धारण किया था।

2. इस प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2000 में, जब एनएसआईसीटी के लिए प्रशुल्क निर्धारित किया गया था, भूस्वामी पत्तन के रूप में जेएनपीटी को देय समस्त रायल्टी, जेएनपीटी और एनएसआईसीटी के बीच बीजोटी अनुमति की अनुमति व्यवों के रूप में अनुमति दी गई थी, चूंकि समीक्षा का उद्देश्य जैसाकि प्राधिकरण द्वारा उस समय नोटिस में बताया गया था एनएसआईसीटी द्वारा इस प्राधिकरण के समस्त प्रस्तुत अनुमतियाँ बातायात और वास्तविक बातायात के संदर्भ से समीक्षा भर करना था, यह प्राधिकरण 2005 में की गई समीक्षा में रायल्टी में हस्ताक्षेप करने से दूर रहा। यह पुनः दोहराया जाता है कि नवम्बर 2000 में पारित इस प्राधिकरण के आदेश में विशेष रूप से यह प्राकाशन किया गया था कि प्रशुल्क का निर्धारण उपलब्ध करवाए गए अनुमतियों के आधार पर था और प्रशुल्क को जब कभी वास्तविक डाटा उपलब्ध हो, समायोजित किया जा सकेगा। मूल आदेश में सन्मिहित अपवाद के ही अनुसरण में पिछली समीक्षा की गई थी और रायल्टी वाले पहलू पर विचार करने से बचा गया।

3. पोत परिवहन, सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय (एमएसआरटीएच) ने अपने पत्र संख्या-14018/38/2003-पीजी दिनांक 22 नवम्बर 2005 के द्वारा इस प्राधिकरण से, एनएसआईसीटी के मामले में, लागत की एक भट्ट के रूप में पूरी रायल्टी की अनुमति देने पर स्पष्टीकरण मांगा था, तथ्यस्थान मंत्रालय ने यह इनिटियोटिव किया कि एनएसआईसीटी मामले में टीएएमपी के निर्णय से यह आमास होता है कि संशोधित प्रशुल्क भार्गदारियों से हटकर याता गया था और एक अन्य निजी टर्मिनल प्रवालक द्वारा इसे एक पूर्व उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया था।

4. जैसा कि उपर कहा गया है, इस प्राधिकरण का यह आशय नहीं था कि भार्गदारियों से अलग चला जाए और केवल एनएसआईसीटी को, रायल्टी अनुमति व्यव मानने की अनुमति प्रदान की जाए। परिस्थितिवाद, इस प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया था कि नोटिस, सुनवाई आदि सम्बुद्धि प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद, नए भार्गदारियों के संदर्भ से प्रशुल्क की समीक्षा की जाए।

5. हमारे पत्र दिनांक 14 नवम्बर 2005 द्वारा एनएसआईसीटी को सूचित किया गया था कि यह एनएसआईसीटी के प्रशुल्क की एक पक्षीय समीक्षा में एनएसआईसीटी द्वारा देय समस्त रायल्टी राशि को वर्ष 2005-2006, 2006-2007 और 2007-2008 वर्षों के लिए लागत रूप में लिए जाने की स्थीकार्यता तक 22 जुलाई 2005 के आदेश की समीक्षा पर अपनी राशि दे। एनएसआईसीटी का उत्तर संक्षेप में, निम्नलिखित है :-

- (i) आदेश एक पक्षीय समीक्षा का विषय नहीं हो सकता, आदेश की समीक्षा का एकमात्र संभावित प्रबोजन, प्रशुल्क निर्धारण की प्रक्रिया में एनएसआईसीटी को अनुमति लागत के एक छोटे भाग को पलटना लगता है।
- (ii) महापत्तन न्यास अधिनियम, टीएएमपी द्वारा अपने ही आदेश की एक पक्षीय समीक्षा करने हेतु स्पष्ट रूप से कोई प्राकाशन नहीं करता। केवल संशोधित प्रशुल्क भार्गदारी ही नीति के प्रश्नों पर निदेश जारी करने के लिए सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तदनुसार धारा 3.3.2 के प्राकाशनों के अनुसार, जो टीएएमपी को एक पक्षीय समीक्षा आरंभ करने की अनुमति देता है, महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों के पूरी तरह बाहर है। अतएव, टीएएमपी द्वारा अपने ही आदेश की एक पक्षीय समीक्षा विधि के प्राधिकार के बिना है और बिना अधिकार देते हैं।
- (iii) जुलाई 2005 का आदेश पारित होने से पहले, एनएसआईसीटी ने दिनांक 30 जून 2005 के अपने पत्र के द्वारा विस्तार से यह समझाया था कि वहों न इसके प्रशुल्क में बृद्धि की जाए। एनएसआईसीटी द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार करके और जुलाई 2005 के अपने आदेश के द्वारा 10(ix) (ग) में उन्हीं कारणों को रिकार्ड करते हुए टीएएमपी ने समस्त रायल्टी को लागत के रूप में अनुमति प्रदान की है। स्पष्ट रूप से, आदेश एनएसआईसीटी द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर ध्यान पूर्वक विचार करके और भार्गदारियों के अनुरूप व्यापक विचार विषर्ण के बाद यह आदेश पारित किया गया है और अधिक समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। जुलाई 2005 के आदेश की समीक्षा के लिए कोई आधार पर समस्त रायल्टी
- (iv) संशोधित प्रशुल्क भार्गदारियों की धारा 2.8.1 (रायल्टी राजस्व भाग की लागत के रूप में स्थीकार्यता के बारे में) पहले से ही अस्तित्व में थी और टीएएमपी द्वारा जुलाई 2005 के आदेश में उस पर पूर्ण रूपेण विचार किया गया था। धारा 2.8.1 की कथित धारा में कोई संशोधन नहीं हुआ है। जुलाई 2005 के आदेश ने विशिष्ट आधार पर समस्त रायल्टी

राशि को लागत रूप में अनुमत किया था और वह स्वयं प्रशुल्क की एक एक्षीय समीक्षा का भागला था, दर्तमाल प्रक्रिया का प्रयोग्यन वही है, यदि एक एक्षीय समीक्षा ही आधार-पत्र है और जुलाई में कटौती अनुमत करने का कारण है, तो निम्नते में किसी अन्य परिवर्तन की अनुपरिवर्ति में पांच माह के बाद भी वही कारण आवश्यक रूप से लागू होना चाहिए।

(v) संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 3.1.8 (प्रशुल्क वैधता अवधि के बारे में) विशिष्ट रूप से प्राक्षाल करती है कि एक बार निर्वाचित किया गया प्रशुल्क 3 वर्ष तक लागू रहेगी और उक्त अवधि में कोई भी समीक्षा, मार्गदर्शियों द्वारा टीएमपी में निहित शक्तियों के बाहर होगी।

(vi) दिनांक 22 जुलाई 2005 के आदेश में यह संशोधन करने को टीएमपी कोई सांविधिक शक्ति प्राप्त नहीं है, जो करने की अनुमति यांगी जा रही है, वह मुश्किल से पांच माह पहले पारित कर्मान आदेश की न केवल समीक्षा करना, बल्कि उसमें अधिकार कोई रूप से संशोधन करना है। यह अधिकार क्षेत्र के बाहर है और प्रस्तावित समीक्षा विधि के प्राधिकार के बाहर है, न तो सरकार को न ही टीएमपी को, मार्गदर्शियों में निर्वाचित 3 वर्ष की सुनिश्चित अवधि से पहले तात्कालिक आधार पर इस प्रशुल्क आदेश में अधिनियम के अन्तर्गत संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि टीएमपी को आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है, तो भी कोई सुपरिणाम देने हेतु न तो परिवर्तियों में कोई परिवर्तन नहीं है और न ही संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 3.3.2 के अन्तर्गत पर्याप्त कारण ही हैं।

उपर्युक्त को देखते हुए एनएसआईसीटी ने इस प्राधिकरण से जुलाई 2005 के आदेश की समीक्षा के लिए कोई कायम न उठाने का अनुरोध किया है।

6. उपर्युक्त उत्तर प्राप्त करने के बाद प्रभावित पक्ष एनएसआईसीटी को सुनवाई का अवसर देने हेतु 13 जनवरी 2006 की तिथि निर्धारित की गई थी। एनएसआईसीटी उपरिवर्त दुआ और उसने दिनांक 9 जनवरी 2006 के अपने उपरोक्त पत्र में सन्निहित तर्कों पर पुनः जोर दिया और आग्रह का दिया था कि इस प्राधिकरण को अपने ही आदेश की समीक्षा करने का कोई सांविधिक अधिकार नहीं है और संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों पर भारत सरकार द्वारा जारी नीति निर्देश में कोई विधिक प्राक्षाल नहीं था, तथापि एनएसआईसीटी ने मुद्रे के पक्ष में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किए। यह एक और अवसर दिया गया तो एनएसआईसीटी ने सूचित किया कि जो कुछ उसने दिनांक 9 जनवरी 2006 के अपने पत्र में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दिया है, उसके अतिरिक्त उसके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ भी नहीं है।

7. अनिवेष्ट से यह स्पष्ट है कि समीक्षा करने के लिए इस प्राधिकरण की सांविधिक शक्तियों के बारे में समान तर्क पिछली बार भी, जिस पर 22 जुलाई 2005 के आदेश में कार्रवाई की गई थी, उठाए गए थे, जैसाकि पिछले आदेश में कायम रखा गया था, अन्य बातों के साथ, “दर निर्वाचित करने की शक्ति में समीक्षा करने की शक्ति भी समिल है” यह एक स्वीकृत रिक्ति है कि प्रशुल्क प्रस्तुत डाटा पर आधारित है और यदि ये डाटा ही ठीक नहीं हैं तो समीक्षा का अधिकार उसमें अन्तर्मिहित है। यदि किसी कारण से प्राधिकरण द्वारा कोई त्रुटि हो गई है तो मार्गदर्शियों का पूरी तरह अनुपालन करने के लिए प्रशुल्क की भी समीक्षा की जा सकती है। इसी प्रकार से परत्तों के लिए भी यह खुला है कि परिवर्तियों में परिवर्तन के आधार पर ये समीक्षा के लिए प्राधिकरण के पास आ सकते हैं।

8. एनएसआईसीटी का वह दृष्टिकोण जिसका गलत अर्थ लगाया गया, यह था, कि एनएसआईसीटी द्वारा की गई सभी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद ही जुलाई 2005 का आदेश पारित किया गया था, कि केवल उसी आधार पर प्राधिकरण ने अदा की गई सम्पूर्ण रायलटी को लागत के रूप में अनुमत किया था, कि व्यापक विचार विमर्श के बाद ही आदेश पारित किया गया था और इसीलिए समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसाकि पहले ही कपर स्पष्ट किया जा चुका है, जुलाई 2005 का आदेश पारित करते समय रायलटी को अनुमत करने पर विचार करने का प्रस्तुत इस समाचार कारण से, कोई मुद्रा तक नहीं था, कि समीक्षा, दृक्षापूर्वक अनुमानित लागत और वास्तविक लागत के बिन्दु पर की गई थी और इसीलिए, एनएसआईसीटी को विशिष्ट नोटिस दिए किना न तो प्राधिकरण ने रायलटी के मुद्रे पर विचार किया और न ही वह ऐसा कर ही सकती थी।

9. एनएसआईसीटी ने आगे दावा किया है कि पिछला आदेश सभी आवश्यक डाटा पर विचार विमर्श करने के बाद ही पारित किया गया था, इसीलिए, यह समीक्षा अनावश्यक थी। जैसाकि उपर पहले ही कहा जा चुका है, दर्तमान समीक्षा केवल रायलटी तक ही सीमित है, जो पिछले आदेश में विवारणीय विवेद-दस्तू नहीं था। वास्तविकता दो यह है कि पिछले आदेश में यह बहुत ही स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया था कि प्राधिकरण रायलटी के विषय में यथारिति बनाए रख रहा है, और पूरी रायलटी को व्यय के रूप में अनुमत किया जा रहा था, ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ग्रासांगीक समय पर विचार किए जाने के लिए वह कोई मुद्रा ही नहीं था।

10. एनएसआईसीटी ने धारा 111 और सरकार द्वारा दिए गए निरेश का संदर्भ दिया है, प्राधिकरण यह स्पष्ट करता है कि सरकार की ओर से ऐसा कोई निरेश नहीं है और यह प्राधिकरण नए मार्गदर्शियों से अपनी अनुसूचिता व्यक्त करते हुए अपने पिछले आदेश की एक पूर्णीय समीक्षा कर रहा है कि क्योंकि संबद्ध लोगों के बीच यह गलतफहमी हो रही है कि टीएएमपी अपने ही मार्गदर्शियों का पालन नहीं कर रहा है, एनएसआईसीटी प्रस्तुत करता है कि मार्गदर्शियों की धारा 3.3.2 भारत सरकार द्वारा जिन अधिकार क्षेत्र तैयार और अनुमोदित की गई है, जियोंकि अधिनियम में समीक्षा के लिए प्राधिकार प्रदान नहीं किया गया था इसलिए यह मार्गदर्शियों में भी प्रदान नहीं किया जा सकता। हम इस विन्दु पर पहले भी विदार विभाग कर चुके हैं कि प्रशुल्क निर्धारित करने का अधिकार, समीक्षा करने का अधिकार भी है, और उसी के अनुसार में, यह मार्गदर्शियों में प्रदान किया गया था, और जो कुछ सरकार ने मार्गदर्शियों में निर्देशित किया है वह यह है कि इस प्रकार की समीक्षा एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए, किसी भी स्थिति में, अधिनियम के अन्तर्गत, सरकार की नीति निर्माता शक्तियों पर कोई बंधन नहीं हो सकता।

11. रायल्टी के बारे में प्राधिकरण ने तथ्यों और परिस्थितियों को नोट किया है जिनकी वजह से मार्गदर्शियों में रायल्टी के बारे में प्रावधान सम्प्रसिद्धि किया गया। चेन्नई कन्टेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीसीटीएल) ने इस प्राधिकरण और भारत सरकार के विवरण दिल्ली उच्च न्यायालय में अन्य बातों के साथ, मार्गदर्शियों के अधाव में इस प्राधिकरण को संविधान से ऊबर करने वाले प्राक्तानों का विरोध करते हुए, और यह माना करते हुए कि जब चेन्नई पत्तन के लिए सीसीटीएल ने बोली लगाई थी तब बोली की शर्तों में वह प्रावधान कि प्रशुल्क के बराबर आने के लिए रायल्टी व्यय के रूप में अनुमत नहीं की जाएगी, नहीं था; और कि इस प्रकार की शर्त के बाद बोलीयों के लिए लगाई गई थी; और कि सीसीटीएल को सम्पूर्ण रायल्टी अनुमेय व्यय के रूप में अनुमत की जानी चाहिए, एक रिट याचिका दायर की थी। इस मामले को निपटाने के लिए सीसीटीएल के अनुरोध पर मानसीय पोत परिवहन मंत्री जी के कक्ष में एक बैठक रखी गई थी, उस बैठक में इस प्राधिकरण के अध्यक्ष, सीसीटीएल के अध्यक्ष जो उस समय एनएसआईसीटी के तात्कालिक अध्यक्ष भी थे, सीसीटीएल के वकील और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे, उस बैठक में पीएसएसआईसीटी भी उपस्थित था जिसके पास तृतिकोरिन पत्तन न्यास का अनुबंध था और जिसने मद्रास उच्च न्यायालय में एक रट याचिका दायर कर रखी थी। 5 अगस्त 2003 को हुई इस बैठक में विस्तार से बताया गया था कि सरकार की नीति के अनुसार पत्तनों ने महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 42 के अधीन, वर्धी के प्रधालन और प्रबंधन के लिए उन बोलीदाताओं को ढेके (अनुबंध) प्रदान किए जिन्होंने उच्चतम रायल्टी / राजस्व भाग को (अनुमेय व्यय) मानने की अनुमति दी है, यदि उन्हें उस मद में कोई हानि होती है और उन बोलीदाताओं को केवल दूसरी उच्चतम बोली से अधिक रायल्टी / राजस्व भाग के अतिरिक्त भाग को छोड़ना होता। इन शर्तों और निर्धारणों के अनुसार सीसीटीएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में से अपनी रिट याचिका वापिस ले ली और उसने दूसरे उच्चतम बोलीदाता के बराबर राजस्व भाग की अनुमति देते हुए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यद्यपि सीसीटीएल शौर एनएसआईसीटी का अस्तित्व अलग-अलग है, मूल रूप से हन दोनों का स्थानित और नियन्त्रण यी एड और पोर्टस के पास ही है। उस समय भी और आज भी इनका अध्यक्ष साझा है। इन परिस्थितियों में एनएसआईसीटी के लिए मार्गदर्शियों को चुनोती देने या "रायल्टी" के मुद्दे पर बहस करने में अब बहुत विलम्ब हो चुका है। मार्गदर्शियों में रायल्टी के बारे में प्राक्तानों की यही पृष्ठमूलि थी।

12. लंबे तर्क-वितर्क के बाद उपस्थित सभी पक्ष इस बात पर सहमत हो गए कि यही उचित और न्यायसंगत होगा कि उन पत्तनों के लिए जहाँ अनुबंध सरकार की नीति घोषित होने से पहले प्रदान कर दिए गए थे वहां पत्तनों के बोलीदाताओं को अगली उच्चतम बोली की सीमा तक रायल्टी / राजस्व भाग को (अनुमेय व्यय) मानने की अनुमति दी है, यदि उन्हें उस मद में कोई हानि होती है और उन बोलीदाताओं को केवल दूसरी उच्चतम बोली से अधिक रायल्टी / राजस्व भाग के अतिरिक्त भाग को छोड़ना होता। इन शर्तों और निर्धारणों के अनुसार सीसीटीएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में से अपनी रिट याचिका वापिस ले ली और उसने दूसरे उच्चतम बोलीदाता के बराबर राजस्व भाग की अनुमति देते हुए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यद्यपि सीसीटीएल शौर एनएसआईसीटी का अस्तित्व अलग-अलग है, मूल रूप से हन दोनों का स्थानित और नियन्त्रण यी एड और पोर्टस के पास ही है। उस समय भी और आज भी इनका अध्यक्ष साझा है। इन परिस्थितियों में एनएसआईसीटी के लिए मार्गदर्शियों को चुनोती देने या "रायल्टी" के मुद्दे पर बहस करने में अब बहुत विलम्ब हो चुका है।

13. उपर्युक्त आधार पर इस प्राधिकरण ने, जेएनपीटी से उसके पत्र सं. सीपीडी/सीएम/टीएएमपी/2005/1352, दिनांक 20 दिसम्बर 2005 के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर, दूसरी उच्चतम बोली के बराबर केवल रायल्टी को, गणनाओं में अनुमत करने का निर्णय किया है।

14. किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए और इस प्राधिकरण के आशय को ढीक-ढीक प्रतिविवित करने के लिए संशोधित मार्गदर्शियों के अन्तर्गत अनुमेय सीमा तक रायल्टी पर विचार करके वर्ष 2005-2006, 2006-2007 और 2007-2008 के लिए एनएसआईसीटी की आधारित लागत का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक है।

15. प्रशुल्क निर्धारण के लिए संशोधित मार्गदर्शियों के अनुसार 29 जुलाई 2003 से पहले निर्धारित बोलियों के मामले में, प्रशुल्क की गणना में, प्रशुल्क निर्धारण हेतु भूस्यामी पत्तन को निजी प्रधालन क्वारा द्वारा देय, अगले उच्चतम बोलीदाता द्वारा उद्घृत अधिकतम राशि के बराबर, रायल्टी / राजस्व भाग को लागत के रूप में शामिल करना चाहिए ताकि इस मद के कारण, जिसे गणना में शामिल नहीं किया जा रहा हो, होने वाली हानि से बचा जा सके। एनएसआईसीटी और जेएनपीटी के बीच लाइसेंस लाइसेंस अनुबंध पर 3 जुलाई 1997 को हस्ताक्षर किए गए थे।

16. रायल्टी मॉडल में बोली-मूल्य आरम्भिक मुगतान और रायल्टी मुगतान से सम्बद्ध होते हैं। यूकी बोली मूल्य एक से अधिक हैं और सफल बोलीदाता का द्वयन एनपीटी आकलन के आधार पर किया गया था, दूसरे उच्चतम बोलीदाता द्वारा उद्घृत (राशि) तक संगणना में विचार किए जाने के लिए रायल्टी सुनिश्चित करने हेतु इसी प्रकार के विश्लेषण का अनुसरण किया जाना है। इस मामले में दूसरे उच्चतम बोलीदाता द्वारा उद्घृत राजस्व-क्रम का एनपीटी, कथित रूप से 163.816 करोड़ रुपये है जो एनएसआईसीटी की बोली के एनपीटी का 69.50% पाया गया है। इसका अर्थ हुआ कि एनएसआईसीटी द्वारा उद्घृत रायल्टी के अधिकतम 69.50% का, संशोधित प्रशुल्क

मार्गदर्शियों के अनुसार ; प्रशुल्क संगणन के लिए स्वीकार किया जा सकता है, बश्ते, यदि इस सीमा तक इसे नहीं अनुमत किया गया तो एनएसआईसीटी को हानि होगी ।

17. सीसीटीएल से संबंधित एक ऐसे ही मामले में, राजस्व और स्वीकार्य लागत और प्रतिलिप्त के बीच अन्तर दूर करने के लिए हानि को इस प्रयोजन से लिया गया था । इस मामले में, कोई स्पष्ट हानि नहीं दिखाई देगी । लागत विवरणी में दर्शाया गया अधिशेष जैसाकि दिनांक 22 जुलाई 2005 के आदेश के पैराग्राफ 10 (xvi) के अन्तर्गत रिकार्ड है, अगले बढ़क के लिए प्रशुल्क के समायोजन की शर्त के कारण, निजी टर्मिनल प्रचालक द्वारा स्थायी आधार पर नहीं रखा जाना है ।

18. तदनुसार, 2005-2006, 2006-2007 और 2007-2008 इन 3 वर्षों के लिए एनएसआईसीटी द्वारा देय रायल्टी राशि, प्रशुल्क संगणन प्रयोजन से 69.50% ही ली जानी है । ऊपर किए गए विचार विवरण के प्रकाश में, पिछली प्रक्रियाओं में विचारित लागत विवरणी को संशोधित कर दिया गया है । संशोधित लागत विवरणी संलग्नक के रूप में संलग्न है । विवरणी द्वारा उद्घाटित परिणाम, संक्षेप में नीचे दी गई सारणी में दर्शाएं गए हैं:

क्रम सं.	वर्ष	अधिशेष (+) / घाटा (-) (लाख लाखों में)	अधिशेष (+) / घाटा (-) (प्रचालन आय का %)
(1)	2005-2006	16,808/-	44.3
(2)	2006-2007	14,725/-	38.8
(3)	2007-2008	12,201/-	32.1
(4)	वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक के लिए प्रचालन आय के % के रूप में औसत अधिशेष		38.4

उपरोक्त सारणी में देखा जा सकता है कि प्रचालन आय की प्रतिशतता के रूप में विचाराधीन सीमा वर्षों के लिए औसत शुद्ध अधिशेष, इससे पिछले औसत अधिशेष लगभग 30% की तुलना में 38.4% है ।

19. इस संदर्भ में यहाँ यह नोट करना उचित होगा कि ऊपर चर्चित अधिशेष स्थिति वर्ष 2005-2006 से वर्ष 2007-2008 तक के तीन वर्षों की अवधि के संबंध में है । चूंकि किसी भी प्रशुल्क समायोजन का प्रभाव केवल भविष्य में ही होगा और वर्ष 2005-2006 समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, अगले दो वर्षों के लिए प्रासंगिक शुद्ध अधिशेष स्थिति, अगले दो वर्षों अर्थात् 2006-2007 और 2007-2008 के लिए प्रासंगिक प्रशुल्क में आरम्भ की जानी है ।

20. वर्ष 2000 में अधिसूचित प्रशुल्क के आधार पर वर्ष 2006-2007 और 2007-2008 के लिए कुल अधिशेष स्थिति 26,926 लाख रुपये है । जुलाई 2005 में आदेशित प्रशुल्क कमी का प्रभाव 11258 लाख रुपये रहने का अनुमान है । यह उल्लेखनीय है कि चूंकि एक पक्षीय समीक्षा लागत और राजस्व अनुमानों के बोटे अनुमानों और बाह्य निष्कर्षों के आधार पर की गई थी जुलाई 2005 के आदेश में अधिशेष स्थिति की पूर्ण सीमा तक प्रशुल्क में कमी समाहित नहीं थी ।

इस कारण, वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक तीन वर्षों के लिए लगभग 19857 लाख रुपये का अधिशेष, जुलाई 2005 के आदेश के पैरा 10(xvi) में निहित शर्त के अन्तर्गत असमायोजित छोड़ दिया गया था । वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-2008 के लिए अधिशेष की तदनुरूप राशि, जो 8414 लाख रुपये होती है, को उन्हीं शर्तों के अधीन असमायोजित छोड़ना न्याय संगत लगता है । इसका अर्थ हुआ कि वर्ष 2006-2007 और 2007-2008 के लिए लगभग 7253 लाख रुपये का शुद्ध अधिशेष समायोजन के लिए उपलब्ध है । इस शुद्ध अधिशेष को समायोजित करने के लिए, जुलाई 2005 में अनुमोदित प्रशुल्क को भावी प्रभाव से लगभग 12% घटाने की आवश्यकता है ।

21.1 परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों से यह प्राधिकरण, 3 अगस्त 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित एनएसआईसीटी के दरमान को 12% घटाने का निर्णय करता है ।

21.2. एनएसआईसीटी को अपना दरमान तदनुसार सुधारने का निर्देश दिया जाता है ।

21.3. संशोधित दरमान, इस आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से 30 दिन बीतने के बाद प्रभाव में आएगा और 22 जुलाई 2005 के पिछले आदेश में प्रशुल्क की फैवता अवधि तक फैव रहेगा ।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2005/असा.]

1161 97/2006-2

नहुए थे इन्टरनेशनल कन्टेनर टर्मिनल लिमिटेड की लागत विवरण

卷一百一十五

	(ii) प्रमुख निवारण के लिए संवेदित मार्च वर्षीयों के अनुतान 2005-06 और इसके बाद की अवधि के लिए निवारित शुल्क पर 15% प्रतिलापन स्थीकार्य प्रतिलापन के अनुतान के बाद शुल्क अधिसेव / घाटा / आय के प्रतिलापन के रूप में शुल्क अधिसेव / घाटा / स्थीकार्य लागत के रूप में राष्ट्रीय का अनुतान अनुगत करने के बाद और स्थीकार्य प्रतिलापन के बाद) कलप VI में अनुपरा स्थीकार्य प्रतिलापन के अनुतान वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक और 2005-06 से 2007-08 तक के वर्षों के लिए कुल प्रबालनीय आय की प्रतिलापन के रूप में औसत शुल्क अधिसेव / घाटा						8123	7522	7024
V	-304	7481	14418	13225	12581	12074	9901	7487	
VI	-1.80%	25.58%	38.70%	34.91%	33.15%	31.81%	28.33%	19.68%	
VII									
VIII	-162	3741	7208	6612	6291				
IX		वाच वर्षी	के लिए	संचयी	23671	4734	4734	4734	
X						16806	14725	12201	
XI						44.3%	38.5%	32.1%	
XII									38.4%

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th April, 2006

No. TAMP/15/2005-NSICT.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby reviews its earlier Order dated 22 July, 2005 relating to the Scale of Rates of Nhava Sheva International Container Terminal Limited as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports
Case No. TAMP/15/2005 - NSICT

ORDER(Passed on this 7th day of March 2006)

This Order is issued fixing a revised tariff, after reviewing the order dated 22nd July 2005 relating to revision of the Scale of Rates of Nhava Sheva International Container Terminal

(NSICT) which was, published in the Gazette of India on 3rd August 2005. The Order of 22nd July 2005 became necessary on account of the fact that, for the previous tariff fixation, this Authority had taken into consideration the estimated revenue based on traffic that was projected to this Authority by NSICT, and it was found that the estimate was far less than actual traffic witnessed during the period, and the increased revenue accordingly. However, at the time of the earlier review, despite repeated requests, NSICT did not furnish any data or information and, therefore, the review was done based on the information available with this Authority, the relevant details obtained from JNPT and the details which had been furnished by NSICT earlier, at the time of the fixation of tariff in 2000. Analysis of the cost positions for the years 2005-2006, 2006-2007 and 2007-2008 indicated an average revenue surplus of 30.20%, in addition to recovery of the permissible return on Capital Employed. For the reasons stated in the said Order, this Authority fixed a revised tariff reducing the earlier rates effectively by about 12.85%.

2. When the tariff for NSICT was fixed by this Authority in the year 2000, the entire royalty payable to JNPT, as the landlord Port, under the relevant BOT agreement between JNPT and NSICT, was permitted as allowable expenses. At the review undertaken in 2005, since the object of the review, as stated in the notice by the Authority at that time, was only to review with reference to the estimated traffic projected by NSICT to this Authority – and the actual traffic, this Authority refrained from interfering with the royalty. It is reiterated that the Order of this Authority passed in November 2000 specifically provided that the fixation of tariff was based on the estimates made available and that the tariff could be adjusted on actual data, when available. It is in pursuance of that exception, contained in the original Order, the last review was undertaken; and hence abstention from dealing with the royalty aspect.

3. The Ministry of Shipping, Road Transport & Highways (MSRTH), vide its letter No. PR-14019/38/2003-PG dated 22nd November 2005, had sought clarification from this Authority on allowing full royalty as an item of cost in the case of NSICT. Subsequently, the Ministry pointed out that the decision of TAMP in NSICT case gave an impression of deviation from the revised tariff guidelines and was quoted as a precedent by another private terminal operator.

4. As stated above, it was not the intention of this Authority to deviate from the guidelines and permit only NSICT to treat the royalty as allowable expenditure. In the circumstances, it was decided by this Authority to review the tariff with reference to the new guidelines, after following proper procedure, like a notice, hearing, etc.

5. NSICT was notified vide our letter dated 14th December 2005 to furnish its comments on reviewing the Order dated 22nd July 2005, to the extent of admissibility of the entire royalty amount payable by NSICT, taken as cost for the years 2005-2006, 2006-2007 and 2007-2008, in the *suo motu* review of tariff of NSICT. The reply of NSICT is summarised below:

- (i). The Order cannot be a subject of *suo motu* review. The only feasible purpose of the review of the Order seems to be to reverse a small part of the cost allowed to NSICT in the process of tariff fixation.
- (ii). The Major Port Trusts Act does not explicitly provide any provision for TAMP to review its own order *suo motu*. Only the revised tariff guidelines permit the Government to issue directions on questions of policy. Accordingly, in terms of clause 3.3.2, which provides TAMP to initiate *suo motu* review, is entirely outside the powers vested in the Central Government under Section 111 of the MPT Act. Therefore, *suo motu* review of its own order by TAMP is without authority of law and without jurisdiction.
- (iii). NSICT, vide its letter dated 30th June 2005, before passing the Order of July 2005, set out in detail as to why the tariff should not be increased. TAMP, after consideration of submissions made by NSICT and recording the reasons for the same in paragraph 10

- (ix) (c) of the Order of July 2005, allowed the entire royalty amount paid as cost. Obviously, the Order has been passed after carefully considering the submissions made by NSICT and after comprehensive application of mind in conjunction with the guidelines. There is no necessity for a further review. No ground is set out for reviewing the Order of July 2005.
- (iv). Clause 2.8.1 of the revised tariff guidelines (regarding admissibility of royalty revenue share as cost) was already in existence and fully considered by TAMP in July 2005 Order. There is no amendment to the said clause 2.8.1. The July 2005 Order allowed the entire royalty amount as cost on the specific basis and that case was a *suo motu* review of tariff itself. The present proceeding purports to the same thing. If a *suo motu* review is the very ground and reason for allowing the deduction in July, the same reasoning must necessarily apply 5 months later in the absence of any other changes in the position.
- (v). Clause 3.1.8 of the revised tariff guidelines (regarding tariff validity period) specifically provides that tariff once fixed will be in force in 3 years and any review within the said period would be beyond the powers vested by the guidelines on the TAMP.
- (vi). TAMP has no statutory power to enter into this revision of the Order dated 22nd July 2005. What is being sought to be done is to materially amend an existing Order passed barely 5 months ago and not to review it. This is beyond the jurisdiction and the proposed review is without authority of law. Neither the Government nor TAMP is empowered under the Act to amend this tariff Order momentarily before the prescribed period of 3 years, as set out in the guidelines. Even if assuming that TAMP is entitled to review the Order, there has been no change in the situation to entail any good and sufficient reasons under clause 3.3.2 of the revised tariff guidelines.

In view of the above, NSICT has urged this Authority not to take any steps to review its Order of July 2005.

6. After receipt of the above reply, a date for hearing the affected party, viz. NSICT, was fixed on 13th January 2006. NSICT appeared and reiterated its arguments contained in the above letter of 9th January 2006, and the substance of the contention was that this Authority did not have statutory powers to review its own Orders and that the policy direction issued by the Government of India on the revised tariff guidelines was devoid of any legal authority. NSICT, however, did not advance any arguments on merits of the issue. When one more opportunity was offered, NSICT intimated that it had nothing to submit further, than what had already been submitted in the Written Submissions dated 9th January 2006.

7. It is clear from the record that identical arguments in regard to the statutory power of this Authority to review were raised on the last occasion, which was dealt with in the Order dated 22nd July 2005. As already held in the earlier Order, *inter alia*, "power to fix the rate also includes the power to review". It is an accepted position that tariff is based on the data submitted and, if these data are incorrect, a right of review is inherent. The tariff can also be reviewed to comply substantially with the guidelines, if, for any reason, the Authority had made an error. Similarly, it is open for the Ports also to approach the Authority for a review, on the ground of change of circumstances.

8. The misconceived contention of NSICT is that the Order of July 2005 was passed after considering all submissions made by NSICT, that it is only on that basis the Authority allowed the entire royalty paid as cost, that the Order was passed after comprehensive application of mind and that, therefore, there is no necessity for review. As already clarified above, the question of consideration of permitting the royalty was not even an issue while passing the Order of July 2005, for the simple reason that the review was undertaken strictly on the point of the cost estimated and the actuals and, therefore, without a specific notice to NSICT, the Authority did not consider, nor could it have considered, the point of royalty.

9. NSICT further contended that the previous Order had been passed taking into consideration all necessary data and, therefore, the review was unnecessary. As already stated above, the present review is only restricted to "royalty", which was not a subject matter considered in the previous Order. As a matter of fact, in the previous Order, it had been very specifically stated that the

Authority was maintaining *status quo* in the matter of royalty and that full royalty was being allowed as expenses. This was done only since this was not an issue considered at the relevant time.

10. NSICT has made a reference to Section 111 and a directive by the Government. The Authority makes it clear that there is no such directive from the Government and the Authority is *suo motu* reviewing its earlier Order, in order to conform to the new guidelines since it is creating misunderstanding amongst concerned people that TAMP is not following its own guideline. NSICT submits that clause 3.3.2 of the guidelines has been framed and approved without any jurisdiction by the Government of India, inasmuch as an authority to review was not provided in the Act and, therefore, cannot be provided in a guideline. We have already dealt with this point earlier that the authority to fix tariff is also an authority to review, and it is in pursuance of that it is provided in the guidelines; and all that what the Government has directed in the guidelines is that such review also should be through a consultative process. In any event, there cannot be fetter on the policy-making power of the Government under the Act.

11. In regard to the royalty, the Authority has taken note of the facts and circumstances which led to the inclusion of the provision regarding royalty in the guidelines. Chennai Container Terminal Pvt. Ltd. (CCTL) had filed a Writ Petition in the High Court of Delhi against this Authority and the Government of India, inter alia contending the provisions constituting this Authority as *ultra vires* of the Constitution, for lack of guidelines, and that since the bid conditions, when CCTL bid for the Chennai Port, did not contain a provision that "royalty" will not be allowed as expenses for arriving at the tariff, that such a condition was imposed only for later bids and that CCTL should be allowed the entire royalty as allowable expenditure. To settle this matter, at the request of CCT, a meeting was held in the chambers of the (then) Hon'ble Minister for Shipping. Present at the said meeting were the Chairman of this Authority, the Chairman of CCTL – who was then the Chairman of NSICT also, CCT counsel and other officials. Also present at the meeting was PSA-SICAL, who had the contract for Tuticorin Port Trust and who had filed a Writ Petition in the High Court of Madras. At the meeting held on 5th August 2003, it was explained that, as per the Government policy, the Ports awarded contracts for operation and management of berths, under Section 42 of the Major Port Trust Act, to a bidder who offered to pay the highest royalty / revenue share. If the bidder, who succeeds, is subsequently permitted by this Authority to recoup the royalty by way of allowable expenditure in the fixation of tariff, it would, in effect, mean that the bidder is paying out the royalty only out of the revenue earned by him from the trade.

12. After prolonged arguments, all parties present agreed that it would be fair and reasonable that, for those Ports where contracts were entered into before the Government policy was known, the Ports would be permitted to treat that part of the royalty / revenue share up to the limit of the next highest bid, if they incur any loss on this account, and those bidders would have to only forego the extra part of the royalty / revenue share, over and above the second highest bid. According to these terms and conditions, CCTL withdrew the Writ Petition filed in the Delhi High Court and submitted a revised proposal permitting revenue share equivalent to the second highest bidder. Even though CCTL and NSICT are two different entities, they are both substantially owned and controlled by the P&O Ports, with a common Chairman – then as well as now. In the circumstances, it is too late for NSICT to challenge the guidelines or argue about the "royalty" issue. This was the background for the provision regarding royalty in the guidelines.

13. On the above basis, this Authority has decided to allow in its calculations only royalty equivalent to the second highest bidder, as per information received from JNPT vide its letter no.PPD/CM/TAMP/2005/1352 dated 20 December 2005.

14. In order to remove any confusion and to correctly reflect the intention of this Authority, it is necessary to reassess the estimated cost position of NSICT for the years 2005-2006, 2006-2007 and 2007-2008, by considering royalty to the extent permissible under the revised guidelines.

15. As per the revised guidelines for tariff fixation, in case of bids finalised before 29th July 2003, the tariff computation must take into account royalty / revenue share payable by the private operator to the landlord Port as cost for tariff fixation, so as to avoid the likely loss on account of this item not being taken into account, subject to maximum of the amount quoted by the next highest bidder. The Licence Agreement entered into between NSICT and JNPT was signed on 3rd July 1997.

16. In the royalty model, the bid values relate to initial payment and royalty payment. Since the bid values are more than one and the successful bidder was selected based on the NPV

assessment, a similar analysis is to be followed to decide the royalty to be considered in computation to the extent quoted by the second highest bidder. The NPV of the revenue stream quoted by the second highest bidder in this case is reported to be at Rs.163.616 crore, which is found to be 69.50% of the NPV of the bid of NSICT. This means, a maximum 69.50% of the royalty quoted by NSICT can be admitted for tariff computation purpose, as per the revised tariff guidelines, provided NSICT would incur loss if it is not allowed to this extent.

17. In a similar case relating to CCTL, 'loss' for this purpose was taken to mean gap between the revenue and admissible costs and return. In this case, there may not be any apparent loss. But the surplus depicted in the cost statement is not to be retained by the private terminal operator on a permanent basis, because of the stipulation of adjustment of tariff for the next cycle, as recorded under paragraph 10 (xvi) of the Order dated 22nd July 2005.

18. Accordingly, the royalty amount payable by NSICT for the 3 years, viz. 2005-2006, 2006-2007 and 2007-2008, is to be taken at the level of 69.50% for the purpose of tariff computation. In the light of the discussion above, the cost statement considered in the earlier proceeding has been modified. The modified cost statement is attached as an Annex. The result disclosed by the statement is summarised as shown in the table given hereunder:

S. No.	Year	Surplus (+) / Deficit (-) (Rs. in Lakhs)	Surplus (+) / Deficit (-) (% of operating income)
(1).	2005-2006	16,808/-	44.3
(2).	2006-2007	14,725/-	38.8
(3).	2007-2008	12,201/-	32.1
(4).	Average surplus as % of operating income for the years 2005-2006 to 2007-2008.		38.4

It can be seen from the above table that the average net surplus for the three years under consideration, as a percentage of operating income, stands revised to 38.4%, as against the earlier average surplus of about 30%.

19. It may be relevant here in this context to note that the surplus position discussed above pertains to the three year period from 2005-06 to 2007-08. Since any tariff adjustment can have prospective effect only and the year 2005-06 is drawing to a close soon, the net surplus position relevant for the next two years is to be set off in the tariff relevant for the two years i.e., 2006-07 and 2007-08.

20. The aggregate surplus position for years 2006-07 and 2007-08 is Rs.26926 lakhs based on the tariff notified in the year 2000. The impact of tariff reduction ordered in July 2005 is estimated to be around Rs.11258 lakhs. It is noteworthy that the Order of July 2005 did not envisage reduction in tariff to the full extent of surplus position since the *suo motu* review was carried out based on approximation and extrapolation of the cost and revenue estimates. For this reason, a surplus of around Rs.19857 lakhs for the three years 2005-06 to 2007-08 was left unadjusted subject to the stipulation contained in para 10 (xvi) of the Order of July 2005. It appears reasonable even now to leave the corresponding amount of surplus for the years 2006-07 and 2007-08 which comes to Rs.8414 lakhs unadjusted subject to the same condition. This means, a net surplus of around Rs.7253 lakhs for the years 2006-07 to 2007-08 is available for adjustment. In order to adjust this net surplus, the tariff approved in July 2005 is required to be reduced prospectively by about 12%.

21.1. In the result, and for the reasons given above, this Authority decides to reduce the Scale of Rates of NSICT notified in the Gazette of India on 3 August 2005 by 12%.

21.2. The NSICT is directed to amend its Scale of Rates accordingly.

21.3. The revised Scale of Rates shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of this Order in the Gazette of India and will remain valid for the tariff validity period prescribed in the earlier Order of 22nd July 2005.

Annex

COST STATEMENT OF NHAVA SHEVA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL LIMITED

Sr. No.	Particulars	Financial years (Rs. In lakhs)					
		2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01	2004-05
I	Throughput in TEUs	944999	943226	1201119	1230555	1232470	1232470
	OPERATING INCOME						
	Income from Container Handling	18486	26846	34288	35122	35183	35183
	Income from Storage and others	1679	2281	2859	2735	2740	2740
	Other Income	17	19	28	28	28	28
	Total Operating Income	20182	29246	37175	37885	37951	37951
II	OPERATING COST						
	Equipment Running Costs	1786	2578	3258	3803	4115	4362
	Operating & Direct Labour	748	807	856	907	961	1019
	Maintenance Labour	253	271	287	304	323	342
	Staff Welfare	88	98	103	110	116	123
	General Operations	484	532	596	610	617	625
	Royalty	407	1771	1847	1882	1882	1882
	Property Costs	198	198	210	222	236	250
	IT/Communications	174	184	201	219	239	260
	Operations Equip. Downtn.	3985	3986	3986	3986	3986	3986
	Equipment Hire	205	220	233	247	262	278
	Technical Service Fees	0	0	0	0	0	0
	Sub Total (a)	83309	10025	11657	14080	15116	16832
	Non-operating Depreciation	259	327	328	328	328	328
	Misc Exp.	310	310	310	310	255	24
	Management & General Overheads	560	584	634	676	722	770
	Sub Total (b)	1129	1221	1272	1314	1304	1174
	TOTAL (I) (a+b)	9438	11256	12236	15044	16720	17754
III	SURPLUS (I+II)	10744	17890	24246	22481	21220	20197
IV	Computation of Return						
	(I) For the period 2004-05 to 2004-05						
	Preference Share Capital (found nil in its Annual accounts)	13000	13000	13000	13000	13000	13000
	Equity and debt considered in the ratio 1:1 of the capital employed after it being funded by the preference share.	30453	29487	26255	24382	22389	22389
	Equity share holder funds	30453	28487	26255	24382	22389	22389
	Debt	1820	1820	1820	1820	1820	1820
	14% dividend on preference shares	3198	2991	2757	2560	2351	2351
	10.5% as the cost of the debt subject to debt equity in the ratio of 1:1 of the capital employed allowed for the year 2000-01 to 2004-05	6091	5697	5251	4876	4478	4478
	Total return for the period 2000-01 to 2004-05	11108	10508	9828	9257	8649	8649

	(ii) 15% Return on capital employed for the period 2005-06 onwards as per the revised guidelines for tariff fixation.					8123	7522	7024
V	NET SURPLUS/DEFICIT after admissible Return and payment of royalty (III+IV)	-364	7481	14418	13225	12581	12074	9991
VI	NET SURPLUS/DEFICIT AS A PERCENTAGE OF INCOME (after allowing payment of royalty as admissible cost and after admissible return)	-1.80%	25.58%	38.79%	34.91%	33.15%	31.81%	26.33%
VII	Average net surplus/ deficit as a percentage of total operating income for the years 2000-01 to 2004-05 and 2005-06 to 2007-08 in addition to the admissible return allowed at VI above							18.68%
VIII	50% of net surplus/ benefit for spreading it over the subsequent years at the time of tariff review/ revisions (V * 50%)	-182	3741	7209	6612	6291		
IX	Setting off 50% of the benefit / loss accrued during the years 2000-01 to 2004-05 over the next five years					23671	4734	4734
X	Net surplus in addition to admissible Return, payment of royalty as cost item and after adjustment of past benefit/ loss over the subsequent years(V+IX)						16808	14725
XI	Net surplus as a percentage of total operating income for the years 2005-06 to 2007-08 in addition to the the return allowed and after setting off 50% of the benefits/ losses accrued in the past five years						12201	
XII	Average net surplus as a percentage of total operating income for the years 2005-06 to 2007-08 in addition to the the return allowed and after setting off 50% of the benefits/ losses accrued in the past five years (XI)						44.3%	38.8%
								32.1%
								38.4%